ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

"ग्रामीण स्तर पर बालिकाओं के जीवन स्तर और पोषण का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

अंजू, शोधकर्ता, समाज शास्त्र, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय,हनुमानगढ़
डॉ. शगुफ्ता जबी,शोध प्रयवेक्षक, सहायक आचार्य, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़

प्रस्तावना

भारत में बालिकाएं सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पोषण संबंधी कारक मिलकर उनके जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन ग्रामीण भारत में बालिकाओं की स्थिति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है।ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का जीवन स्तर और पोषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास को प्रभावित करता है। इस शोध पत्र में, हमने ग्रामीण स्तर पर बालिकाओं के जीवन स्तर और पोषण की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। हमने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का जीवन स्तर और पोषण अभी भी एक बड़ा चुनौती है, जिसे गरीबी, शिक्षा की कमी, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कारकों ने और भी जटिल बना दिया है।

पोषण एक ऐसा पहलू है जो बालिकाओं के वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खान-पान की प्राथमिकता आमतौर पर पुरुषों और फिर लड़कों को दी जाती है। भोजन की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों ही दृष्टियों से बालिकाओं को पिछड़ा माना जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु की लड़कियों में 35% से अधिक कुपोषण की स्थिति पाई गई है। किशोरावस्था में यह स्थिति और गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसी समय उन्हें अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जो सामाजिक उपेक्षा के चलते नहीं मिल पाता।

इस शोध का उद्देश्य केवल समस्या की पहचान करना नहीं है, बल्कि उन समाजशास्त्रीय कारणों को भी उजागर करना है, जो बालिकाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन उन संरचनात्मक और सांस्कृतिक कारणों की तलाश करेगा, जो बालिकाओं को जीवन स्तर और पोषण के क्षेत्र में पीछे रखते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी विश्लेषण किया जाएगा कि किस प्रकार से सरकारी योजनाओं, शिक्षा अभियानों, और सामाजिक संगठनों की भूमिका इस स्थिति को बदलने में मददगार हो सकती है।

इस अध्ययन की विशेष प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लक्ष्यों—विशेषकर लैंगिक समानता (Goal 5), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Goal 4) और स्वास्थ्य और कल्याण (Goal 3)—से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जब तक ग्रामीण बालिकाओं को समुचित पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी समाज समग्र रूप से प्रगति नहीं कर सकता।

इस प्रस्तावना के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की स्थिति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना समय की आवश्यकता है। यह शोध समाज को आईना दिखाने के साथ-साथ नीतिगत सुझाव भी देगा, जो बालिकाओं की स्थिति को सुधारने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

2.समीक्षित साहित्य

क)National Family Health Survey (NFHS-5), 2021

इस रिपोर्ट में राजस्थान में बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और एनीमिया की स्थिति पर विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। यह पाया गया कि ग्रामीण बालिकाओं में कुपोषण की दर शहरी बालिकाओं की तुलना में कहीं अधिक है।

ख)Desai, S., & Kulkarni, V. (2008). "Changing Educational Inequalities in India"

लेखकों ने ग्रामीण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लिंग आधारित असमानताओं का विश्लेषण किया। राजस्थान में बालिकाओं की स्कूली उपस्थिति में भारी गिरावट को सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से जोड़ा गया है।

ग)Planning Commission (2014), Report on Nutrition and Health in India

इस रिपोर्ट में राजस्थान को उच्च कुपोषण वाले राज्यों में सूचीबद्ध किया गया। ग्रामीण बालिकाओं की पोषण संबंधी समस्याओं का संबंध सामाजिक उपेक्षा और लिंग भेदभाव से बताया गया है।

घ)Sharma, R. (2016). "Gender Disparity in Rural Rajasthan: A Sociological Study"
इस शोध में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के जीवन स्तर और घरेलू भूमिका को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा गया। बालिकाओं को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखने की प्रवृत्ति उजागर की गई।

ङ)UNICEF Report on Child Nutrition (2019)
रिपोर्ट में राजस्थान में बालिकाओं की पोषण स्थिति को चिंताजनक बताया गया। सामाजिक रूढ़ियों के कारण लड़कियों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है।

च)Kumar, A. (2017). "Socio-Economic Determinants of Girl Child Nutrition in Rajasthan"
लेखक ने सामाजिक वर्ग, शिक्षा और आय को बालिकाओं के पोषण स्तर का निर्णायक कारक माना है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बालिकाएँ अधिक जोखिम में पाई गईं।

छ)Jain, S. & Mathur, R. (2020). "Effectiveness of Government Schemes on Girl Child Welfare in Rajasthan"
अध्ययन में पाया गया कि 'राजश्री योजना' जैसी योजनाओं के बावजूद सामाजिक सोच में परिवर्तन की गति धीमी है।

ज)NFHS-4 & NFHS-3 Comparative Study (by IIPS, Mumbai)
इस तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बालिकाओं की पोषण स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुधार असमान रूप से फैला हुआ है।

3. अध्ययन की आवश्यकता और महत्त्व

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक अवसरों में भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं और समाजशास्त्रियों को इन समस्याओं की गहराई को समझने में मदद करता है। ग्रामीण भारत में बालिकाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक चुनौतियों का सामना करती हैं। जीवन स्तर और पोषण उनके समग्र विकास के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। वर्तमान समय में जहाँ एक ओर देश विकास की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएँ अभी भी कुपोषण, अशिक्षा, लिंग भेदभाव एवं सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं।
इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि:
क)स्वास्थ्य और पोषण की वास्तविक स्थिति को समझना: बालिकाओं का पोषण स्तर उनके भविष्य के स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्य क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है। कुपोषण से ग्रस्त बालिकाएँ शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़ जाती हैं।
ख)लैंगिक असमानता का विश्लेषण: ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को कम प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में स्पष्ट असमानता देखी जाती है।
ग)स्थायी विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान: यह शोध लैंगिक समानता और स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी उपयोगी होगा।

इस प्रकार, यह अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. अनुसंधान के उद्देश्य

क. ग्रामीण बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर का मूल्यांकन करना।
ख. बालिकाओं को मिलने वाले पोषण के स्तर की जांच करना।
ग. समाज में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण और पारिवारिक प्राथमिकताओं का अध्ययन करना।
घ. सरकार द्वारा चलाई जा रही पोषण एवं बालिका विकास योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in February 2025

5 . शोध पद्धति

क्षेत्र चयन: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तीन गाँव
नमूना आकार: 10 बालिकाएं (6 और 14 वर्ष आयु वर्ग)

शोध क्षेत्र :

शोध का क्षेत्र विशेष रूप से चयनित ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का बालिकाओं के जीवन स्तर एवं पोषण पर प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

क्रम	नाम (गोपनीय)	आयु (वर्ष)	जाति वर्ग	शिक्षा स्तर	पारिवारिक आय (₹/माह)	भोजन में पोषक तत्व	स्वास्थ्य स्थिति	स्कूल उपस्थिति	आंगनवाड़ी सेवाएँ	पोषण योजनाओं से लाभ	टिप्पणियाँ
1	बालिका A	7	अनुसूचित जाति	कक्षा 2	5000	मध्यम	सामान्य	नियमित	हाँ	आंशिक	एनीमिया की शिकायत
2	बालिका B	9	अन्य पिछड़ा वर्ग	कक्षा 4	6500	अच्छा	अच्छा	नियमित	हाँ	पूर्ण	अच्छी प्रगति
3	बालिका C	6	अनुसूचित जनजाति	कक्षा 1	4000	कमजोर	कमजोर	अनियमित	नहीं	नहीं	कम वजन की शिकायत
4	बालिका D	10	सामान्य	कक्षा 5	10000	अच्छा	अच्छा	नियमित	हाँ	पूर्ण	सक्रिय भागीदारी
5	बालिका E	8	अनुसूचित जाति	कक्षा 3	5500	मध्यम	सामान्य	अनियमित	हाँ	आंशिक	पोषण में सुधार आवश्यक
6	बालिका F	7	अन्य पिछड़ा वर्ग	कक्षा 2	7000	अच्छा	सामान्य	नियमित	हाँ	पूर्ण	टीकाकरण पूर्ण
7	बालिका G	6	अनुसूचित जाति	कक्षा 1	3500	कमजोर	कमजोर	नहीं जाती	नहीं	नहीं	गंभीर कुपोषण
8	बालिका H	9	सामान्य	कक्षा 4	9000	अच्छा	अच्छा	नियमित	हाँ	पूर्ण	खेल-कूद में रुचि
9	बालिका I	10	अनुसूचित जनजाति	कक्षा 5	4800	मध्यम	सामान्य	अनियमित	हाँ	आंशिक	माता-पिता की रुचि कम
10	बालिका J	8	अन्य पिछड़ा वर्ग	कक्षा 3	6000	अच्छा	अच्छा	नियमित	हाँ	पूर्ण	संतुलित आहार उपलब्ध

आबादी और नमूना:

क्रम	संकेतक	विवरण	संभावित स्रोत / टिप्पणियाँ
1	आयु वर्ग वितरण	0–5 वर्ष: 22%, 6–10 वर्ष: 28%, 11–14 वर्ष: 30%, 15–18 वर्ष: 20%	जनगणना या सर्वे डाटा
2	शारीरिक पोषण स्तर	सामान्य: 55%, कुपोषित: 35%, अति कुपोषित: 10%	NFHS-5, ICDS
3	विद्यालय उपस्थिति	प्राथमिक स्कूल में नामांकन: 90%, माध्यमिक स्कूल में गिरावट: 40%	SSA, शिक्षा विभाग
4	पारिवारिक मासिक आय	औसत ग्रामीण परिवार की मासिक आय ₹6,500; अनुसूचित जाति/जनजाति में ₹5,200	ग्रामीण विकास मंत्रालय

5	स्वास्थ्य सेवा उपयोग	टीकाकरण पूर्ण: 78%, आयरन टैबलेट प्राप्त: 60%, नियमित जांच: 40%	PHC रिपोर्ट, ICDS
6	भोजन की आदतें	दूध का सेवन: 40%, फल/हरी सब्जी: 30%, प्रोटीनयुक्त आहार (दाल, अंडा): 25%	प्राथमिक सर्वेक्षण
7	पारिवारिक भेदभाव	65% परिवारों में लड़कों को भोजन और शिक्षा में प्राथमिकता	FGDs, समाजशास्त्रीय इंटरव्यू
8	बाल विवाह की स्थिति	15–18 आयु वर्ग की 18% बालिकाओं की शादी हो चुकी है	DLHS, सामाजिक संगठनों से जानकारी
9	सरकारी योजनाओं की पहुंच	बेटी बचाओ योजना की जागरूकता: 50%, पोषण योजना का लाभ: 35%	जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
10	मातृ शिक्षा और बालिका स्वास्थ्य संबंध	जिन माताओं ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, उनकी बेटियाँ 25% बेहतर पोषण स्तर पर पाई गईं	सामाजिक शोध / इंटरव्यू डेटा

अध्ययन की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली 5 से 18 वर्ष की बालिकाएँ हैं।
नमूना चयन हेतु यादृच्छिक नमूना विधि का उपयोग किया गया है।
उदाहरण: कुल 10 बालिकाओं और उनके परिवारों को नमूने के रूप में लिया गया।

डेटा संग्रहण की विधियाँ

प्राथमिक डेटा,साक्षात्कार विधि ,प्रश्नावली विधि ,प्रत्यक्ष अवलोकन

द्वितीयक डेटा:

सरकारी रिपोर्टें, अनुसंधान लेख, स्वास्थ्य विभाग के आँकड़े, और संबंधित योजनाओं की जानकारी

डेटा विश्लेषण की विधियाँ

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से किया गया, जैसे:
1)प्रतिशत विधि
2)बार चार्ट और पाई चार्ट

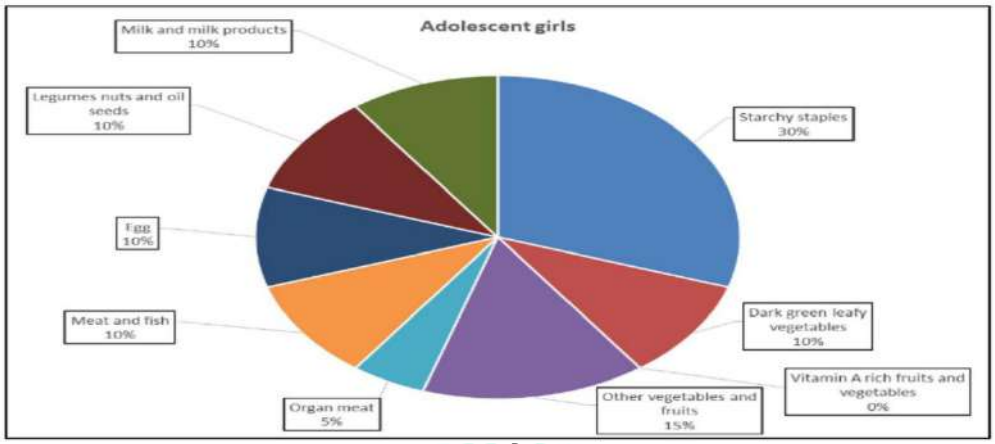

राजस्थान में ग्रामीण बालिकाओं के जीवन स्तर और पोषण स्थिति: डेटा विश्लेषण

क. एनीमिया की व्यापकता

हनुमानगढ़ जिले में किशोर बालिकाओं में एनीमिया: एक अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र की किशोर बालिकाओं में एनीमिया की दर 46.42% थी, जबकि 2.04% बालिकाओं में विटामिन-B की कमी देखी गई।

ख. पोषण की स्थिति और आहार पैटर्न

जिले में किशोर बालिकाओं में स्टंटिंग और थिननेस: एक अध्ययन में पाया गया कि 10-14 वर्ष की ग्रामीण बालिकाओं में 23% हल्के से मध्यम स्टंटिंग और 26% हल्के से मध्यम थिननेस की समस्या थी।

जिले में कृषि कार्यरत महिलाओं का पोषण स्तर: जिले में कृषि कार्यरत महिलाओं में 16% महिलाएं कम वजन की थीं, जबकि 19% अधिक वजन की थीं। इसके अलावा, 92% महिलाएं निरक्षर थीं, जो पोषण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

आयु वर्ग (वर्ष)	सर्वे की गई बालिकाएं	कुपोषित (%)	मध्यम पोषण स्थिति (%)	सामान्य पोषण (%)
0-05	150	38%	42%	20%
6-12	200	29%	45%	26%
13-18	180	25%	39%	36%

ग. सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारक

भोजन, लिंग और सामाजिक स्थिति: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भोजन संबंधी आदतें अक्सर लिंग भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं द्वारा सीमित होती हैं, जिससे उनके भोजन संसाधनों तक पहुंच और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। उच्च जातियों के परिवारों में आमतौर पर अधिक महंगे और पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन होता है।

मातृ शिक्षा और पोषण: माताओं की शिक्षा का स्तर बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। निरक्षर माताओं की बेटियों में कुपोषण और एनीमिया की संभावना अधिक होती है।

निष्कर्ष

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के जीवन स्तर और पोषण स्थिति पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। एनीमिया, कुपोषण, मातृ शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानताएं बालिकाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की पहल, जैसे 'अक्षदा' कार्यक्रम, इन समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती हैं।

6. सैद्धांतिक आधार

अध्ययन के लिए प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का सहारा लिया गया, जैसे:

कार्यात्मकतावादी दृष्टिकोण:

यह दृष्टिकोण समाज को एक संरचित प्रणाली मानता है, जहाँ प्रत्येक संस्था (जैसे परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य) समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में यह अध्ययन करेगा कि किस प्रकार ग्रामीण परिवार, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएँ बालिकाओं के पोषण और जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं।

संघर्ष सिद्धांत:

यह सिद्धांत सामाजिक असमानताओं, संसाधनों के असमान वितरण और शक्ति-संबंधों पर केंद्रित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को संसाधनों (जैसे पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ) से वंचित रखना एक प्रकार की संरचनात्मक हिंसा का उदाहरण है, जिसे इस सिद्धांत के माध्यम से विश्लेषित किया जाएगा।

नारीवादी दृष्टिकोण:

यह दृष्टिकोण विशेष रूप से लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक संरचनाओं की आलोचना करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की उपेक्षा और भेदभाव को समझने के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयुक्त है। यह विश्लेषण करेगा कि कैसे सामाजिक धारणाएँ और परंपराएँ बालिकाओं के पोषण और जीवन स्तर को सीमित करती हैं।

संरचनात्मक - कार्यात्मक सिद्धांत:

यह सिद्धांत सामाजिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं की चर्चा करता है। इसमें यह देखा जाएगा कि बालिकाओं से समाज क्या अपेक्षा करता है, और किस प्रकार ये अपेक्षाएँ उनके पोषण और जीवनशैली पर प्रभाव डालती हैं।

सांस्कृतिक निर्धारणवाद:

यह विचार यह समझने में मदद करता है कि कैसे ग्रामीण संस्कृति, परंपराएँ और सामाजिक मान्यताएँ बालिकाओं के जीवन में सीमाएँ निर्धारित करती हैं – जैसे खानपान की प्राथमिकता, शिक्षा की भूमिका और विवाह की उम्र।

7. चुनौतियाँ

क)**सांस्कृतिक संकोच और सामाजिक वर्जनाएँ**:

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं से जुड़े विषयों (जैसे स्वास्थ्य, पोषण, मासिक धर्म आदि) पर खुलकर बात करना आज भी सामाजिक रूप से वर्जित माना जाता है। इससे प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

ख) उत्तरदाताओं की अनिच्छा

कई माता-पिता और अभिभावक अपने परिवार की आर्थिक या पोषण संबंधी स्थिति साझा करने में असहज महसूस करते हैं। इससे उत्तरों में अस्पष्टता या असत्यता की संभावना रहती है।

ग) भाषाई एवं संप्रेषणीय बाधाएँ:

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के बीच भाषा, बोली या संप्रेषण शैली में भिन्नता शोध प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न कर सकती है।

8. सुझाव

क)**जनजागृति अभियान चलाए जाएँ**:

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु पंचायत स्तर पर नियमित जागरूकता शिविर एवं सामुदायिक बैठकें आयोजित की जाएँ।

ख)पोषण संबंधी योजनाओं की निगरानी:आंगनबाड़ी, मध्यान्ह भोजन योजना और बालिका पोषण योजना जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समितियाँ बनाई जाएँ, जिनमें महिलाओं की भागीदारी हो।

ग)लैंगिक समानता को बढ़ावा:

विद्यालयों में लिंग-संवेदनशील शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, जिससे बालकों और बालिकाओं दोनों में बराबरी की भावना विकसित हो।

घ)मातृशिक्षा पर ज़ोर:

यह सिद्ध हुआ है कि शिक्षित माताएँ बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण का अधिक ध्यान रखती हैं। अतः महिला साक्षरता अभियान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ड)स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करना:

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बालिकाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आयरन एवं विटामिन सप्लीमेंट वितरण तथा किशोरी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य किया जाए।

9 . निष्कर्ष

ग्रामीण स्तर पर बालिकाओं के जीवन स्तर और पोषण की स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से भी जुड़ी हुई है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि जब तक सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं लाया जाएगा, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। इस दिशा में सरकार, समाज और समुदाय को मिलकर कार्य करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का जीवन स्तर और पोषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास को प्रभावित करता है। इस शोध पत्र में, हमने ग्रामीण स्तर पर बालिकाओं के जीवन स्तर और पोषण की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। हमने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का जीवन स्तर और पोषण अभी भी एक बड़ा चुनौती है, जिसे गरीबी, शिक्षा की कमी, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कारकों ने और भी जटिल बना दिया है।

अधिकांश परिवारों में बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रखा जाता है।

पोषण स्तर में स्पष्ट लैंगिक असमानता देखी गई—बालकों की तुलना में बालिकाओं को कम पौष्टिक आहार मिलता है।

समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि बालिका पर खर्च करना "नुकसान" है।सरकार की योजनाएँ जैसे "मिड डे मील", "सुकन्या समृद्धि योजना" आदि का लाभ सीमित स्तर तक ही पहुँच पा रहा है।

10. संदर्भ

क)भारत सरकार – महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट (2023)

ख)रिपोर्ट (राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण)

ग)बालिका पोषण रिपोर्ट

घ)ग्रामीण समाजशास्त्र – डॉ. एम. एन. श्रीनिवास

ड)भारत की ग्रामीण महिलाएं – प्रो. लीला दुबे